





# जेएनयू में बाइक की टक्कर से छात्र की मौत परिसर में रात ढाई बजे हुआ हादसा, तीन जख्मी, दो की हालत गंभीर

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में एक मोटरसाइकिल सवारों ने पैदल चलने वाले दो लोगों को टक्कर मार दी, जिससे इस घटना में 20वीं वर्षीय एक छात्र की मौत हो गई। अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना शनिवार-रविवार की रात ढाई बजे की है, जब मोटरसाइकिल सवार दो छात्रों ने गोदावरी छात्रावास की ओर जा रहे थे और छात्रों को जबकि टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि पर्से वाले छात्र की फहचान अंशु कुमार के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि पैदल चल रहे व्यक्तियों की पहचान सचिन शर्मा और मुगांव यादव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, सचिन की हालत गंभीर है, वहीं मृगांक स्थिर अस्था में है और दोनों विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार, मृतक सप्तमी दो छात्र बाइक पर थे, जब उन्होंने सुवह गोदावरी



बस स्टॉप के पास दो अन्य को टक्कर मार दी। मारा गया 22 वर्षीय अंशु कुमार परिसर में सतलुज हाँस्टल में रहता था और रुसी अध्ययन में बीए प्रथम वर्ष का छात्र था। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

बाइक पर बैठे उनके दोस्त 23 वर्षीय विशाल कुमार को भी चोट आई और उनका इलाज चल रहा है। विशाल, जो कि जेन्यू का छात्र नहीं है, और अंशु बिहार के गया में एक ही गांव के रहने वाले हैं। डीजीपी (दक्षिण-पश्चिम) मनोज सी ने कहा

कि उन्हें सुवह-सुवह एस्स ट्रॉमा सेंटर से जेएनयू में दुर्घटना के बारे में फोन आया। उन्होंने बताया कि एक तेज रफ्तार बाइक ने विश्वविद्यालय परिसर के अंदर दो पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी थी।

जांच अधिकारी को सानसानथला भवान में अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने पाया कि बाइक ने दो अन्य छात्रों को टक्कर मारी और बाद में सक्क के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। छात्रों ने अस्पताल ले जाया गया।

घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए अपराध और फोरेंसिक टीमों ने बुलाया गया और अस्पताल व्यक्तियों के खिलाफ लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने से संबंधित भारतीय दंड सर्विसों (एंडीपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना उस समय हुई जब केंटीएम बाइक, जिस पर मृतक और उसकी दोस्त यात्रा कर रहे थे, दो पैदल यात्रियों से टक्कर गई। सतलुज हाँस्टल में रहने वाले अंशु कुमार बाइक चला रहा था। वह बिहार के गया का रहने वाला था। वह अंशु जेएनयू में रुसी भाषा में बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था।



रविवार को राजधानी के चितरंजन पार्क में दुर्गा पूजा उत्सव को लेकर एक कारीगर मार्द देवी दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप देता हुआ। फोटो: रंजन डिमरी

## बवाना से रिठाला मेट्रो स्टेशन जाना हुआ आसान

- मंत्री ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

बवाना गांव के लोगों को अब रिठाला मेट्रो पहुंचना आसान होने के साथ सुविधाजनक हो गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को चार नई इलेक्ट्रिक बस

को रुट 990सी को हरी झंडी दिखाकर शुरूभार किया।

इस अवसर पर इलाज गहराया के लिए रिटाली में सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को बढ़ाने के यह रुट सुरु किया गया है। कैलाश गहलोत ने बवाना चौक को इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस नए बस मार्ट के शुरू होने से दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बवाना गांव, बवाना औद्योगिक क्षेत्र, बरवाला, पूर्व खुर्द, प्रहलादपुर और उसके आसपास के इलाजों में रहने वाले लोगों को आने-जाने के लिए बेहतर परिवहन विकल्प उपलब्ध होंगे।

इस बस मार्ट के शुरू होने से दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बवाना गांव, बवाना औद्योगिक क्षेत्र, बरवाला, पूर्व खुर्द, प्रहलादपुर और उसके आसपास के इलाजों में रहने वाले लोगों को रिठाला मेट्रो स्टेशन आने-जाने में आसानी होगी। इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने



कहा, मुख्यमंत्री अविंदन के जरीवाल के कशल नेतृत्व में, हम दिव्यांकी की परिवहन व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। 990सी बस मार्ट की शुरूआत दिखाई के नामारिकों के लिए सुविधाजनक परिवहन विकल्प प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस बस रुट के शुरू होने से बवाना गांव, बवाना औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के गांवों बरवाला, पूर्व खुर्द और प्रहलादपुर में रहने वाले लोगों को आने-जाने के लिए बेहतर परिवहन विकल्प उपलब्ध होंगे।

## रोहतक मार्ग पर जल निकासी होगी बेहतर

नई दिल्ली | रोहतक मार्ग पर नागारोड़ मेट्रो स्टेशन और टिकरी बॉर्डर के बीच सड़क पर लंगभार का सार्वजनिक बैठक को रोकने के लिए जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा।

पीड़ित्युड़ी मंत्री आतिशी ने अधिकारियों के साथ नागारोड़ मेट्रो से टिकरी बॉर्डर के बीच की सड़क के रिडिङ्गाइनिंग लान पर समीक्षक बैठक की। पीड़ित्युड़ी मंत्री आतिशी ने निर्देश पर इंसीनियर व्याहू हवाएँ एक्सप्रवर्ट्स के साथ सर्व सर्व कर इस प्लॉट स्ट्रेच के रिडिङ्गाइनिंग का विस्तृत प्लान तैयार कर रहे हैं। समीक्षक बैठक में मंत्री आतिशी ने इसके प्रगति की जाँच की। बवाना के मुताबिक, दिल्ली लोक निर्माण विभाग की मंत्री आतिशी ने सड़क की पुर्णसंरचना पर अधिकारियों के साथ एक समीक्षक बैठक की।

## ईडी अधिकारी बनकर लूट ले गए 3.20 करोड़

- जबरन घर में घुसकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस महकमे में हड्डकंप

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

राजधानी के बाबा हरिदास नगर क्षेत्र में बदमाशों ने खुद को ईडी का अधिकारी बताकर लूट को अंजाम दिया।

बवाना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एक कार पकड़ी है, पीड़िती आतिशी ने जिससे 70 लाख रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि बाबा हरिदास नगर इलाके में स्थित एक घर में खुद को ईडी का अधिकारी बताकर लूट को अंजाम दिया।



पुलिस गिरफ्त में मामले का मुख्य आरोपी। और उन्होंने मेरे घर से 3 करोड़ रुपये व्यक्ति ने आरोपितों के घर से लूट लिए हैं। वे दो कारों में आए थे। उन सभी के पास बंदूक थी।

चोरों को अंजाम देने के बाद पुलिस ने बताया कि छह लोग भर आए और उनके हाथों में शर्तात्मक बदलाव आया।

होने पर पीसीआर स्टाफ ने आरोपी को रोका तो वह भाग गया। इसके बाद पुलिस ने बदलाव को दिलाई बदलास को गिरफ्तार कर लिया है।

पकड़े गए व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्टॉल, 4 कारबून और 70 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं। आगे पृष्ठात तरीके से वह चाला हरिदास नगर में डॉक्टरी में शामिल था।

पुलिस ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस टीम आरोपी से लूट में शामिल अन्य लोगों को लेकर पृष्ठात तरीके से कार चला रहा था। संदेह तरीकों की तलाश में कई जगहों पर

साथी लोगों को अंजाम दिया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस टीम आरोपी से लूट में शामिल अन्य लोगों को लेकर पृष्ठात तरीके से कार चला रहा था।

पुलिस ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया।

साथी लोगों को अंजाम दिया गया।

साथी लोगों क





# फिलिस्तीन मुद्दा

## भारत का दृष्टिकोण

फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि, मीडिया तथा कुछ लोगों का अनुमान है कि भारत ने फिलिस्तीनी लक्ष्य का समर्थन करने की अपनी दीर्घकालिक नीति बदल दी है। पिछले सप्ताह इज्जराइल पर हमेशा के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'एक्स' पर इज्जराइल के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कहा था कि भारत इस देश के साथ दुःख के समय खड़ा है। भारत में बहुत से लोगों ने इस बयान को गलती से इज्जराइल पर दृष्टिकोण बदलने की तरह देखा। इसका कारण इज्जराइल के साथ भारत की बढ़ती निकटता तथा नई दिल्ली में मध्य से दक्षिण की ओर झुकी भाजपा सरकार है। लेकिन विश्लेषकों ने इस मामले में जल्दबाजी की। भारत ने हमेशा फिलिस्तीनी जनता तथा फिलिस्तीनियों के न्यायोचित लक्ष्य का समर्थन किया है। उसका मानना है कि फिलिस्तीनियों का अपना देश होना चाहिए जिसमें बाहरी शक्तियों का कोई हस्तक्षेप न हो। लेकिन भारत ने हमेशा दोनों पक्षों की ओर से आतंकवाद तथा बल प्रयोग को अस्वीकार किया है और उसने बातचीत के आधार पर समझौते की पैरवी की है। फिलिस्तीनी लक्ष्य के प्रति भारत का समर्थन निरंतर बना हुआ है। 1974 में भारत ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन-पीएलओ को फिलिस्तीनी जनता के एकमात्र व वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी थी और ऐसा करने वाला वह पहला गैर-अरब देश था। 1988 में भारत ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी थी। 1996 में ही भारत ने फिलिस्तीन के गाजा शहर में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला था। भारत ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमेशा फिलिस्तीनी लक्ष्य का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा-यूएनजीए के 53वें सत्र में 'फिलिस्तीनियों को आत्मनिर्णय का अधिकार'



पर प्रस्ताव पास हुआ था, भारत इसका सह-प्रायोजक था और उसने इसके पक्ष में बोट दिया था। भारत ने अक्टूबर, 2003 में भी यूएनजीए प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें इज़राइल द्वारा अलग करने वाली दीवाल बनाने का विरोध किया गया था।  
लेकिन हमास और फिलिस्तीन उसी प्रकार समानार्थी नहीं हैं जिस प्रकार लिट्टे व श्रीलंका में रहने वाले तमिल एक नहीं थे। जब प्रधानमंत्री ने बयान दिया तो उसमें उन्होंने हमास की हिंसक कार्रवाइयों का समर्थन नहीं किया। ध्रम दूर करने के लिए विदेश मंत्रालय ने संप्रभु फिलिस्तीन राज्य बनाने के अपने आहान की पुष्टि की। प्रवक्ता ने कहा कि मानवतावादी सिद्धान्तों का समर्थन 'जिम्मेदारी' है और भारत का लंबे समय से यही दृष्टिकोण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बाणचौ ने कहा, 'भारत ने हमेशा एक संप्रभु, स्वतंत्र तथा सक्षम फिलिस्तीन राज्य बनाने के लिए सीधे बातचीजें बहाल करने की पैरवी की है जो अपनी सुरक्षित व स्वीकृत सीमाओं में रहे तथा इज़राइल के साथ शांति बनाए रखें।' हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर हमास को आतंकी संगठन नहीं कहा। दोनों पक्षों के बीच चार बार पहले टकराव के बाद हमास ने उस क्षेत्र पर मजबूती से कब्जा कर लिया है जहां वह 2007 से शासन में शामिल था। इस बीच भारत ने अपने नागरिकों को इज़राइल से निकालने के लिए 'आपरेशन विजय' शुरू किया है तथा लोगों को वहां से ले कर उड़ाने भारत आने लगी हैं। अब तक किसी भारतीय की मृत्यु की खबर नहीं मिली है। तेजी से बदलती स्थितियों में भारत सभी 'महत्वपूर्ण पक्षों' के साथ निकट संपर्क बनाए हुए हैं। अब तक भारत का दृष्टिकोण निरंतरता पर आधारित रहा है, लेकिन स्थिति तेजी से बदल रही है। यदि कोई आमूल परिवर्तन होता है तो भारत को अपनी पश्चिम एशिया नीति की समीक्षा की जरूरत पड़ सकती है।

# आम चुनाव के लिए बनती रणनीति

पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे 2024 लोकसभा चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। इससे राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई रणनीतियों का खुलासा होगा।



**पांच** राज्य विधानसभाओं के चुनाव में राजग व 'आई.एन.डी.आई.ए' या 'इंडिया' के बीच विभाजक रेखायें स्पष्ट होती जा रही हैं। हालांकि, राजग उम्मीदवारों की सूचियां जारी करने में 'इंडिया' से आगे हैं जो सुविचारित रणनीति का हिस्सा है। कुछ लेखक इसे 2024 का 'सेमीफाइनल मान रहे हैं, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि मतदाताओं को अभी अपना मन बनाना है। हालांकि, कोई भी पांच राज्यों के चुनावों के परिणामों से ऐसे नतीजे नहीं निकाल सकता है जिनके प्रभाव 2024 लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की सोच पर पड़ता हो।

भाजपा आलाकमान और आरएसएस के सर्वोच्च नेताओं ने पार्टी के चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पेश किया है और उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व मिजोरम में संभावित मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं घोषित किए हैं। भाजपा ने तीन चुनावी राज्यों में 24 सांसदों व 4 केन्द्रीय मंत्रियों को चुनाव में उत्तराने की रणनीति बनाई है जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इससे भाजपा की 'परेशानी और प्रतिबद्धता' प्रकट होती है कि वह इन राज्यों में विजय सुनिश्चित कर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बेहतर विमर्श तैयार करना चाहती है। इसका लक्ष्य मतदाताओं में वर्तमान विधायकों के प्रति नाराजी को 'निष्प्रभावी' करना है ताकि वे इन निर्वाचन क्षेत्रों में नए चेहरों पर पुनर्विचार कर सकें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह यह पार्टी के रणनीतिकारों की सुविचारित रणनीति के साथ एक खोजी तरीका भी है। प्रधानमंत्री मोदी मतदाताओं को आर्किर्षण करने वाले हैं जिनकी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय छवि का प्रयोग मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए हो सकता है। दूसरा, सर्वोच्च पद के लिए अनेक लोगों की उपस्थिति को देखते हुए यह गुटबाजी व विद्रोह रोकने की रक्षात्मक रणनीति है।



इसी कारण भाजपा ने हर राज्य में  
एक मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं घोषित  
किया है।  
मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री  
शिवराज सिंह चौहान पर लगाम लगाने के  
लिए भाजपा आलाकमान ने उम्मीदवारों  
की पहली सूची में नरेन्द्र सिंह तोमर  
प्रह्लाद सिंह पटेल तथा फगन सिंह  
कुलस्ते व सांसदों को उतार कर सबको  
आशर्चयचकित कर दिया। पार्टी के  
अंकलन के अनुसार केन्द्रीय मंत्रियों का  
पूरे राज्य पर प्रभाव है और उनको जनता  
के बीच अपनी राज्यव्यापी स्वीकार्यत  
सिद्ध करनी है। हालांकि, सबाल है कि  
क्या उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्रों पर  
समुचित ध्यान दिया है जो विरोधियों के  
हराने के लिए जरूरी है? राजनीतिक  
विश्लेषकों का विश्वास है कि मंत्री  
आमतौर से बड़े क्षेत्रों पर ध्यान देते हैं  
और अपने गृह राज्यों में किसी खास  
तबके पर विरते ही ध्यान देते हैं। इससे  
उनके लिए समस्या पैदा हो सकती है।

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा  
सकता है कि गांवों तक फैले मतदाताओं  
की इच्छायें बहुत बढ़ गई हैं और वे  
तार्किक आधारों पर अपना फैसला करेंगे  
आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी  
वृद्धि के कारण बेरोजगार नौजवानों की  
इच्छायें भी बहुत ऊँची हैं। इसलिए  
मतदान करते समय वे हर उम्मीदवार के

पूरे पांच साल के कामकाज पर ध्यान देगे। विशेषज्ञों का मानना है कि सांसद या मंत्री विरले ही अपने खास निर्वाचन क्षेत्रों के माइक्रो-प्रबंधन पर ध्यान देते हैं और मध्य प्रदेश में भी उनके समर्थन यह चिन्ता होगी। शिवाराज सिंह चौहान की तुलना में शायद उनका राज्य-स्तरीय दर्जा न हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भाजपा राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों तथा तेलंगाना में सी.एस. राव की 'भारत राष्ट्र समिति'-बीआरएस को सत्ता से हटाने में विफल रहती है तथा मध्य प्रदेश में भी सत्ता खो देती है तो इसका सीधा प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है।

लेकिन यदि ये नतीजे भाजपा के पक्ष में जाते हैं तो उसका लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी की विजय सुनिश्चित करने पर दूना प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके उलट इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और मतदाता राजस्थान, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना में मुख्यमंत्रियों द्वारा बांटी जाने वाली 'खेतां' से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, भाजपा शासित मध्य प्रदेश ने भी जनता को अनेक रियायतें दी हैं। जब मोदी 2024 में देश से अपने लिए बोट देने की अपील करेंगे तथा 'आई.एन.डी.आई.ए' गठबंधन अपना

प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुनने में विफल होगी तो चुनावी परिदृश्य एकदम अलाप होगा। इसका कारण गठबंधन में भीतर टकराव तथा कांग्रेस समेत प्रत्येक क्षेत्रीय क्षत्रप की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ हैं।

राजस्थान में राजे-समर्थकों का किनारे किया गया है। जमीनी रिपोर्ट स्पष्ट है कि गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विन वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल व पूर्व केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर का जमीन स्तर पर राजे की तरह मजबूत संपर्क नहीं है। जयपुर के पूर्व राज-परिवार की दिया कुमारी राजसमंद से सांसद हैं और वे जयपुर के विद्याधर नगर से चुनाव लड़ेंगे। जिसका प्रतिनिधित्व स्वर्गीय ऐरों सिंह शेखावत के दामाद नरपति सिंह राजवी कर रहे हैं। इसके साथ ही मीणा समुदाय के नेता व राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर सीट से लड़ेंगे जहां मीणा-गुजर समुदायों का प्रभुत्व है भाजपा ने राजे को पांच साल तक राजनीतिक अन्नातावास में रखा है जिसमें पूर्व-मुख्यमंत्री एक सीमा तक पार्टी कार्यकर्ताओं से कट गई हैं, हालांकि अन्नी भी उनके समर्थक विधायकों की संख्या सबसे अधिक है।

राजे अपने गृह क्षेत्र, कोटा जिले वे झालावाड़ में भी भाजपा की 'परिवर्त्तन यात्रा' में शामिल नहीं हुई थीं, जबवि-

वहां जनता से उनका लंबे समय से जुड़ा व है। भाजपा अशोक गहलोत के पांच साल के कार्यकाल में आक्रामक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकी क्योंकि आलाकमान युवा पीढ़ी के नेताओं के साथ प्रयोग कर रही थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है जिसका कारण भूपेश बघेल का नेतृत्व है। इंडिया टुडे-सीवीटर सर्वेक्षण के अनुसार भाजपा कांग्रेस से पांच प्रतिशत का अंतर घटा सकती है, पर इससे उसे कांग्रेस को 46 सीट के बहुमत तक पहुंचने से रोकना संभव नहीं होगा। भाजपा ने मुख्यमंत्री के भरीजे विजय बघेल को उम्मीदवार बनाया है जो लोकसभा संसद दै। भाजपा की छत्तीसगढ़ इकाई पिछले पांच साल में बघेल सरकार को धेरने में सफल नहीं हुई है। इससे कांग्रेस को लाभ हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का भाजपा आलाकमान की रणनीति में महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा नेता व पूर्व गज्जवल समूह गणतंत्र एवं प्रिंट

जूदेव ने सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा देने की इच्छा प्रकट की थी, हालांकि वे भाजपा में प्रतिबद्ध रूप से बने हुए हैं। तेलंगाना में राजनीतिक टकराव बहुत तीखा है। मध्य प्रदेश की तरह केन्द्रीय मंत्रियों या सांसदों के 'करिश्मे' पर विश्वास करते हुए भाजपा आलाकमान ने राज्य इकाई की जिम्मेदारी केन्द्रीय मंत्री जी. किशन रेड़ी को सौंपी है। लेकिन उनके सामने पार्टी में व्याप गुटबाजी पर लगाम लगाने की कठोर चुनौती है। केसीआर सरकार के खिलाफ मुख्य बंदी संजय कुमार को हटाने से पार्टी कार्यकर्ताओं को सही संकेत नहीं मिले हैं, हालांकि भाजपा इससे इनकार करती है। भाजपा ने अपने 'गुजरात माडल' पर चलते हुए पुरानी पीढ़ी के नेताओं के स्थान पर नई पीढ़ी के नेताओं को स्थान देने का प्रयोग पूरे देश में किया है। इसके सकारात्मक परिणाम उत्तराखण्ड, गोवा व त्रिपुरा में दिखाई पड़े, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कर्नाटक में भाजपा की हार के पीछे यह प्रयोग एक बड़ा कारण रहा है।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मंत्रियों व सांसदों को चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति भाजपा को लाभ दिलाएगी या उसके विपरीत नतीजे सामने आ सकते हैं।

# कोविड-19 महामारी से मिले सबक

लेह, लद्दाख के मध्य में, चुचोट ब्लॉक के गोंगमा गांव के 17 वर्षीय निवासी मोहम्मद ससेन जैसे किशोरों को कोविड-19 महामारी के दौरान असाधारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विपरीत परिस्थितियों में उनकी यात्राएं ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं जो न केवल प्रासांगिक हैं बल्कि वर्तमान की अनिश्चितताओं से निपटने में भी महत्वपूर्ण हैं।

लेह के जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित चुचोट गांव, जनता कर्फ्यू से कुछ हफ्ते पहले तालाबंदी लागू करने वाले भारत के पहले स्थानों में से एक था। जब महामारी शुरू हुई, तो सैटेन ने खुद को घर से दूर जम्मू में पढ़ाई करते हुए पाया। डर, अनिश्चितता और अपने परिवार से दूरी का उन पर भारी असर पड़ा। ऑल लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के समर्थन के लिए ध्वन्यवाद, सैटेन और अन्य फंसे हुए छात्र अंततः लेह वापस आ गए। घर

जाहिर तौर पर, चाहते थे कि वह अनी पदाई में उत्कृष्टता प्राप्त करे, ऐसा माहौल बनाए जो प्रतिबंधात्मक लगे। तनाव से निपन्ने के लिए सैटेन ने अपने दोस्तों के साथ धूम्रपान करना शुरू कर दिया। फिर भी, उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि धूम्रपान न केवल उनके स्वास्थ्य को बल्कि उनके सपनों को भी खतरे में डालता है, खासकर फुटवॉल के प्रति उनके जुनून को। अपनी भलाई और आकांक्षाओं को प्राथमिकता देने के लिए दूढ़ संकल्पित होकर, उन्होंने धूम्रपान छोड़ने का फैसला किया। हालांकि, उनके सभी दोस्तों को नशे की गिरफ्त से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं लगा। उनके संघर्ष इस बात की स्थायी याद दिलाते हैं कि कैसे महामारी ने युवाओं के जीवन पर प्रभाव छोड़ा है।

लेह में 17 वर्षीय स्कर्मा त्वेंगिंग वांग्याल के परिवार की कहानी उन अप्रत्याशित तरीकों को दर्शाती है जिसमें महामारी ने परिवारों को करीब ला दिया।

आए और उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया। शर्मा ने खुद को घर पर अकेला पाया, डर और तनाव से जूझ रहे थे। उनके छोटे भाई की चिंता, जो उस समय कर्नाटक में था, ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया।  
अनेक चुनौतियों के बावजूद, स्कर्मा और उनके परिवार ने उन विचित्र परिस्थितियों में आशा की किरण खोजी। इस दौरान उनके साझा अनुभवों ने उन्हें करीब ला दिया और उन्हें अपने बंधन में मजबूती मिली। संकर, लेह की एक मां रिचेन डोल्मा ने अपना दृष्टिकोण साझा किया कि महामारी ने उनके परिवार को किसे प्रभावित किया। शुरुआत में अपनी बेटी के स्कूल प्रवेश के लिए जम्मू में एक छोटे से अवकाश की योजना बना रही थीं, लेकिन महामारी की अप्रत्याशित चैपेट के कारण उनका प्रवास बढ़ा दिया गया। इसके कारण 15 दिन का अवकाश लंबे समय तक खिंच गया और उनकी स्थिति की अनिश्चितता ने उन पर बहुत

व्यवहार में आने वाले बदलाव को देखा। कई छात्रों की तरह, उनकी बेटी को भी मॉनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पड़ता था, जिसके लिए मोबाइल फोन की समय अपने फोन पर बहुत अधिक निर्भर नहीं था, तेजी से गेमिंग और स्क्रीन में तलीन हो गया। स्क्रीन की लत के कारण व्यवहार में बदलाव आया, निराशा बढ़ी और पढ़ाई के प्रति उपेक्षा हुई। त्सेतन की कहानी महामारी के दौरान कई परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों को प्रतिबिंబित करती है, किशोरों और उनके परिवारों पर प्रौद्योगिकी की लत ल और अलगाव के महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करती है।

ये कहानियां किशोरों पर महामारी के बहुमुखी प्रभावों को उजागर करती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए, मोहम्मद ससेन और स्कर्पा त्सैरिंग वांग्याल जैसे युवा व्यक्तियों ने लचीलापन प्रदर्शित किया और अनिश्चित समय में हमारा मार्गदर्शन किया। इनमें डोल्मा और त्सेतन कुंजेस जैसे परिवारों ने महामारी की अप्रत्याशित और चुनौतियों का अनुभव किया, तूफान से

## विपक्षी बयानबाजी

## गर्भपात का मद्दा

राजनीतिक मत-मतान्तर सत्ता व विपक्ष के बीच होना स्वाभाविक है, किन्तु ये देश के अंदर तक ही सीमित रहना चाहिए। देश के बाहर न तो सत्ता की आलोचना होनी चाहिए और न ही गंभीर विदेश-नीति या नीतिगत निर्णय के विरोध में विपक्ष को जाना चाहिए। इजराइल-हमास युद्ध के मामले में जब सरकार ने इजराइल का पक्ष लिया और उसके साथ खड़े रहने की बात की तब विपक्ष को सरकार के निर्णय के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें इजराइल से सबक लेना चाहिए जहां युद्धकाल में अलग कैबिनेट का गठन कर उसमें विपक्षी पूर्व सेनाधिकारी को शामिल किया गया है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हमारे आपस में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं किन्तु युद्ध के मामले में हम सरकार का ही समर्थन करेंगे। आश्चर्य है कि भारत में विपक्ष सरकार की आलोचना करते-करते इतना दिशाहीन हो गया है कि उसे देश का हित-अहित भी नजर नहीं आता है। भले ही सीधे-सीधे न कहा जाए, पर विपक्ष के अनेक नेता तुष्टीकरण दृष्टिकोण से केवल अपने बोटबैंक पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। इस प्रकार वे प्रकारान्तर से चुनावी लाभ के लिए भारत में एक समुदाय को भड़काने का प्रयास भी कर रहे हैं।

- शक्तिला महेश नेनावा, इंदौर

— राधुराला महरा गणावा, इपा

## आप की बात

चनावी वादे

कोटा में आत्महत्यायें

-सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

**मध्यप्रदेश**, छत्तीसगढ़ व मिजोरम समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन राज्यों में चुनावी वायदों की होड़ शुरू हो गयी है। कोई पार्टी मुफ्त बिजली दे रही है तो कोई रात-दिन सुरक्षा की बात कर रही है। लेकिन विडंबना है कि चुनाव जीतने के बाद भी पार्टियों द्वारा किए वादे अक्सर जमीन पर नहीं दिखते हैं। बिहार के अनेक क्षेत्रों में जनजातियां मौजूद हैं जो हर तरह से पिछड़ी हुई हैं। आए दिनों उनका अनेक प्रकार से शोषण होता है। किसी समुदाय की स्थिति में शिक्षा पाना बहुत अहम है लेकिन जनजातियों की शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार को प्राथमिकता नहीं मिलती है। वैसे बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदलाली की खबर अक्सर एलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडियम में स्थान पाती हैं। ऐसे में आदिवासियों की शिक्षा व्यवस्था में बदलाली की कल्पना ही की जा सकती है जो सुदूर व दुर्गम इलाकों में अक्सर मीडिया की चकाचौंधरी दूर रहते हैं। वे राज्यों में हाशिये पढ़ते हैं। चुनाव के समय ऐसी बदलाली थोड़ी बहुत उजागर होती है, लेकिन इसका समाधान चुनावी वादों के चकाचौंधरी में ढूब जाता है और जनता ठगा महसूस करती है।

कोटा में इस साल रिकॉर्ड संख्या में छात्रों की मौत होना मानसिक स्वास्थ्य की एक गहरी महामारी की ओर इशारा करता है। इसकी जड़ें सामाजिक-आर्थिक कारकों में हैं जो परिवारों को युवा छात्रों को जबरदस्त तनाव में धकेलने के लिए मजबूर करती हैं। इस वर्ष आठ वर्षों में सबसे अधिक मौतें होने के कारण सरकार को कई उपाय करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वैसे समस्या का संपूर्ण समाधान शिक्षा प्रणाली तथा परीक्षाओं की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करना ही है। इन दूरगमी नीतिगत परिवर्तनों के साथ ही अधिकारियों को ऐसे समाधान तैयार करने की ज़रूरत है जो परीक्षा प्रणाली में तकाल सुधार ला सकें। इसके साथ ही कमज़ोर छात्रों पर खास ध्यान देना ज़रूरी है ताकि वे निराश होकर आत्महत्या जैसे कदम न उठा सकें। कोटा में कोचिंग कालेजों को मुआफे के बजाय छात्रों की अंतर्निहित प्रतिभा तथा उसे बढ़ाने की इमानदार संभावनाओं का आंकलन करना चाहिए। सभी छात्रों की क्षमता एक समान नहीं होती है और नैकरियों व रोजगार के अनेक साधन उनके लिए उपलब्ध हैं।

-मोहम्मद तौकीर, पश्चिमी चंपारण पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से [responsemail.bindinioneer@gmail.com](mailto:responsemail.bindinioneer@gmail.com)











